भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 613
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।
1 श्रावण, 1947 (शक)

डिजिटल-ग्राम परियोजना

613. श्री नारायण तातू राणे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल-ग्राम परियोजना का वर्तमान/संशोधित ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने गांव इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को डिजिटल-ग्राम स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ड.) देश में इस परियोजना के विस्तार के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजना पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(च)**: 'डिजिटल-ग्राम प्रायोगिक परियोजना' की शुरूआत सरकार द्वारा दिनांक 31.10.2018 को की गई थी। इसका लक्ष्य देशभर के 700 गांवों (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले से एक गांव) में शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास सेवाएं, सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट और वित्तीय समावेशन सेवाओं के साथ-साथ सरकार से नागरिक सेवाएं और व्यवसाय से नागरिक सेवाएं प्रदान करना था।

डिजिटल-ग्राम प्रायोगिक परियोजना के तहत, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ज़िले के दो गाँव ऐनावरे और कडावल को शामिल किया गया है। 'डिजिटल ग्राम प्रायोगिक परियोजना' को दिनांक 31 मार्च, 2024 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना पर 62.57 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

4जी/5जी, यूपीआई, डिजीलॉकर, उमंग आदि प्रौद्योगिकियों के विस्तार और प्रसार के परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत में डिजिटल सेवाओं का प्रसार हुआ है।

सरकार को डिजीग्राम के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

****